एम.डी. रईसुल इस्लाम व अन्य।

बनाम

गोकुल मोहन हजारिका व अन्य।

(विशेष अनुमति याचिका (सी) क्रमांक 19188, 2007)

जुलाई 06, 2010

[अल्तमस कबीर और साइरियक जोसेफ, जे.जे.]

असम सिविल सेवा (वर्ग-1) नियम, 1960: आरआर.4, 19 -

असम सिविल सेवा (वर्ग-1) नियम, 1960: आरआर.4 चयन/वरिष्ठता - चयन प्रक्रिया मौजूदा सेवा नियमों के सी पर शुरू हुई - माना गया: मौजूदा नियम चयन प्रक्रिया को नियंत्रित करना जारी रखते हैं, उक्त नियमों में संशोधन के बावजूद इस बीच - एसई इस प्रकार मौजूदा नियम द्वारा शासित होगा - एएसए सर्विसेज (क्लास -1) संशोधन नियम, 1986 - सेवा नियम - वरिष्ठता

असम सिविल सेवा (वर्ग-1) नियम, 1960 के असंशोधित नियम 4 के संदर्भ में एसीएस वर्ग-I और एसीएस वर्ग-II अधिकारियों की प्रत्येक श्रेणी में 30 पदों को भरने के लिए 22.5.1984 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। लिखित परीक्षा आयोजित की गई और परिणाम

22.2.1986 को घोषित किया गया। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के संबंध में एपीएससी द्वारा साक्षात्कार आयोजित किया गया था। एपीएससी द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की एक सूची 22.6.1986 को सरकार को सौंपी गई थी। नियम 4 एफ में संशोधन 21.7.1986 को असम सिविल सेवा (वर्ग-1) संशोधन नियम, 1986 द्वारा किया गया, जिसके तहत एसीएस वर्ग-द्वितीय से एसीएस वर्ग-1 में पदोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया गया था। राज्यपाल और पदोन्नति के लिए 50% का पिछला कोटा बंद कर दिया गया।

129 एसीएस श्रेणी-द्वितीय अधिकारी शामिल, एसीएस क्लास एसी क्लास- I से पदोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को गवर्नर द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया गया था, पदोन्नति के लिए 50% का पिछला कोटा बंद कर दिया गया था और 11.9.1986 को एसीएस क्लास- I कार्यालय के रूप में नियमित रूप से पदोन्नत किया गया था। इसके बाद 22.10.1986 को, उत्तरदाताओं सहित एसीएस क्लास- I ऑफ को वा द्वारा नियुक्त किया गया था।

एपीएससी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सीधी भर्ती। 1.1.1993 को, एक मसौदा वरिष्ठता सूची तैयार की गई थी जिसमें 11.9.1986 को पदोन्नत किए गए सभी 129 अधिकारियों को 45 एसीएस

क्लास- I अधिकारियों से वरिष्ठ के रूप में दिखाया गया था, जिन्हें अक्टूबर 1986 के महीने में विभिन्न तिथियों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया था।

उत्तरदाताओं 1 से 8 ने वरिष्ठता सूची के मसौदे को चुनौती दी, उच्च न्यायालय ने माना कि सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों की वरिष्ठता असंशोधित नियमों द्वारा शासित होगी क्योंकि चयन प्रक्रिया 1986 के संशोधन से पहले शुरू की गई थी। इसलिए विशेष अनुमति याचिका।

विशेष अनुमति याचिका को ख़ारिज करते हुए कोर्ट ने माना कि: 1. एक बार भर्ती के मौजूदा नियमों के आधार पर चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है , इस बीच उक्त नियमों में किसी भी संशोधन के बावजूद उक्त नियम चयन प्रक्रिया को नियंत्रित करना जारी रखेंगे। तदनुसार, सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता, इसमें कोई संदेह नहीं है, असम सिविल सेवा ई (क्लास-एल) नियम, 1960 के नियम 19 के तहत शासित होगी, लेकिन प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए चयन प्रक्रिया को नियम 4 के तहत पूरा करना होगा। नियम 19. उच्च न्यायालय यह निर्देश देने में सही था कि जिन रिक्तियों के लिए विज्ञापन 1984 में प्रकाशित किया गया था, उन्हें असंशोधित नियम 4 के आधार पर भरा जाए, जिसमें पदोन्नत और सीधी एफ भर्ती के बीच कोटा प्रदान किया गया था और सीधी भर्ती के 45 पदों को रखा गया था। वर्ष 1986 के लिए उक्त कोटा प्रणाली को ध्यान में

रखते हुए 129 पदोन्नतियों की सूची में से पहले 45 पदोन्नतियों के ठीक नीचे। [पैरा 27, 28] [747-बी-सी; 746-जी-एच; 747

डॉ. के. रामुलु एवं अन्य। वी. डॉ. एस. सूर्यप्रकाश राव और अन्य। (1997) 3 एससीसी 59, प्रतिष्ठित।

सूरज प्रकाश गुप्ता एवं अन्य। जम्मू एवं कश्मीर राज्य और अन्य। (2000) 7 एससीसी 561; उत्तरांचल राज्य एवं अन्य। वी. दिनेश एच

विपक्ष. रेलवे

कुमार शर्मा (2007) 1 एससीसी 683; उत्तरांचल वन रेंजर्स एसो. (सीधी भर्ती) बनाम यू, पी राज्य। (2006) 10 एससीसी 346; एन.टी. डेविन कट्टी बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग (1990) 3 एससीसी 157, संदर्भित।

केस कानून संदर्भ:

(2000) 7 एससीसी 561	संदर्भित	पैरा 18
(2007) 1 एससीसी 683	संदर्भित	पैरा 18
(2006) 10 एससीसी 346 सी	संदर्भित	पैरा 21
(1990) 3 एससीसी157	संदर्भित	पैरा 22
(1997) 3 एससीसी59	विशिष्ट	पैरा 24, 25, 26

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: एसएलपी (सिविल) संख्या डी 19188, 2007।

गौहाटी उच्च न्यायालय के रिट अपील संख्या 5 में पारित 2004 के निर्णय और आदेश दिनांक 23.5.2007 से।

याचिकाकर्ता के लिए विजय हंसारिया, स्नेहा कलिता, शंकर दिवाते।

पार्थिव गोस्वामी, ए. हेनरी, राजीव मेहता, जे.आर. लुवांग। प्रतिवादी की ओर से रिकू शर्मा (कॉर्पोरेट लॉ ग्रुप के लिए)।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर द्वारा अभिनिर्धारित किया गया।

अल्तमस कबीर, जे. 1. असम सरकार के अनुरोध पर चयन में एसीएस क्लास- I और एसीएस क्लास- II की प्रत्येक श्रेणी में 30 पदों को भरने के लिए सीधी भर्ती मंच के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन करने के लिए, असम लोक सेवा आयोग, जिसे इसके बाद 'एएसपीसी' के रूप में जाना जाता है, ने 22 तारीख को एक विज्ञापन प्रकाशित किया। मई, 1984, असम सिविल सेवा (वर्ग-1) नियम, 1960 के नियम 4 के संदर्भ में उपरोक्त उद्देश्य के लिए। इसके बाद, असम सरकार ने 24 नवंबर को एपीएससी को सूचित किया। तदनुसार, एक संशोधित विज्ञापन 28 नवंबर 1984 को APSC द्वारा प्रकाशित किया गया कि ऊपरी आयु एच सीमा में दो वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया था। उक्त विज्ञापन के अनुसार, एपीएससी द्वारा एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, जैसा कि उपरोक्त नियमों के तहत आवश्यक है, जिसे इसके बाद '1960 नियम' के रूप में

संदर्भित किया जाएगा, 5 जून, 1984 से 1 अगस्त, 1985 के बीच, और उक्त लिखित परीक्षा के परिणाम 22 फरवरी, 1986 को घोषित किए गए थे। इसके बाद एपीएससी द्वारा 25 अप्रैल, 1986 से 30 मई, 1986 तक उन उम्मीदवारों के संबंध में विवे वॉयस टेस्ट आयोजित किया गया था, जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। इसके बाद, APSC ने ACS क्लास-I और ACS क्लास-II श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए 27 जून, 1986 को अनुशंसित उम्मीदवारों की अपनी सूची सरकार को भेजी।

2. 21 जुलाई, 1986 को, सम तारीख की अधिसूचना के माध्यम से, असम सरकार ने 1960 के नियमों के नियम 4(1) और नियम 4(1)(बी) के प्रावधानों में संशोधन किया, जिससे एसीएस से पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई। क्लास-II से एसीएस क्लास I का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाना बाकी था और पदोन्नति के लिए 50 प्रतिशत का पिछला कोटा बंद कर दिया गया था।

3. इस स्तर पर, 1960 के नियमों के नियम 4 का संदर्भ लिया जा सकता है, क्योंकि यह 21 जुलाई के संशोधन से पहले था। 1986, अर्थात्, "नियम 4(1)। इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से होगी, अर्थात्:

(ए) आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा;

(बी) एसीएस (क्लास-II) के उन पुष्ट सदस्यों की पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की है और एसीएस (क्लास-II) नियम, 1962 के नियम 14 के उप नियम (3) के तहत निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है; और

(सी) चयन द्वारा, विशेष मामलों में व्यक्तियों में से। सरकार के मामलों के संबंध में असम सिविल सेवा (वर्ग-II) सेवा के सदस्यों के अलावा; बशर्ते कि खंड (बी) के तहत भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या एक वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत होगी और खंड (सी) के तहत भर्ती किए गए व्यक्ति किसी भी वर्ष दो से अधिक नहीं होंगे; आगे बशर्ते कि खंड (सी) के तहत भर्ती किए गए व्यक्ति किसी भी समय कैडर की कुल ताकत के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

4. जैसा कि ऊपर से स्पष्ट होगा, असंशोधित नियमों के तहत, पदोन्नति के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या एक वर्ष में भरी जाने वाली डी रिक्तियों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत होगी और व्यक्तियों की संख्या होगी उक्त मामलों में खंड (सी) के तहत चयन किसी भी समय कैडर की कुल ताकत के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

5. जब रिक्तियों को भरने की उपरोक्त प्रक्रिया शुरू की जा रही थी, राज्य सरकार ने जैसा कि ऊपर बताया गया है, असम सिविल सेवा (वर्ग-I) (संशोधन) नियम, 1986 द्वारा 1960 के नियमों के कुछ प्रावधानों में

संशोधन किया, इसके बाद इसे '1986 के संशोधन नियम' के रूप में संदर्भित किया गया था, जिन्हें तुरंत लागू होने का निर्देश दिया गया था और इसलिए, इन्हें संभावित संचालन दिया गया था। एफ के साथ जिस संशोधन से हम इस मामले में सीधे तौर पर चिंतित हैं, वह संशोधन नियमों का नियम 2 है, जो इस प्रकार है:

"2. मूल नियमों में, नियम 4 में

(ए) उप-नियम (1) के खंड (बी) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: "(बी) एसीएस (क्लास- II) अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने भर्ती किए जाने वाले वर्ष के जनवरी के पहले दिन एसीएस (क्लास- II) में 5 साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है"।] (बी) उप-नियम (1) के प्रावधान के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -"बशर्ते कि किसी भी कैलेंडर वर्ष में खंड (बी) के तहत भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जा सकती है। बशर्ते कि खंड (सी) के तहत भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी भी वर्ष में नहीं होगीदो से अधिक और किसी भी समय 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा कैडर की कुल ताकत का.

6. नियम 4 के संशोधित प्रावधान, पदोन्नति के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के कोटा को खत्म कर देते हैं और संशोधन के बाद किसी भी कैलेंडर वर्ष में इस तरह से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या उतनी

होगी जितनी राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति के लिए पचास प्रतिशत के निर्धारित कोटा को पदोन्नति के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को इंगित करने के लिए राज्यपाल को दिए गए विवेक से बदल दिया गया था।

7. उपरोक्त चयन प्रक्रिया के अनुसार, याचिकाकर्ताओं सहित 129 एसीएस क्लास- II अधिकारियों को 11 सितंबर, 1986 को नियमित रूप से एसीएस क्लास- I अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था। इसके बाद, 22 अक्टूबर, 1986 को 45 एसीएस क्लास- I अधिकारी, उत्तरदाताओं सहित, एपीएससी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया गया था। 16 दिसंबर, 1989 को, नीति के तहत, राज्य सरकार ने एसीएस वर्ग-द्वितीय श्रेणी को समाप्त करने के लिए एसीएस वर्ग-द्वितीय अधिकारियों को एसीएस वर्ग-I अधिकारियों के साथ विलय कर दिया। इसके अनुसरण में, 1 जनवरी, 1993 को, राज्य सरकार द्वारा आपत्तियां आमंत्रित करते हुए एसीएस क्लास- I अधिकारियों की एक मसौदा ग्रेडेशन सूची प्रकाशित की गई थी। उक्त सूची में, 11 सितंबर, 1986 को पदोन्नत सभी 129 अधिकारियों को 45 एसीएस, क्लास- I अधिकारियों से वरिष्ठ के रूप में दिखाया गया था, जिन्हें अक्टूबर, 1986 के महीने में विभिन्न तिथियों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया गया था।

8. उपरोक्त से व्यथित होकर, प्रतिवादी संख्या 1 से 8 तक ने वरिष्ठता सूची के मसौदे को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की। दिनांक 1 जनवरी, 1993, और 21 जुलाई, 1986 को 1960 के नियमों के नियम 4 में प्रभावी संशोधन। इस स्तर पर इस तथ्य पर ध्यान देना अनुचित नहीं होगा कि याचिकाकर्ताओं और अन्य समान पदों की नियुक्तियाँ 11 सितंबर, 1986 की अधिसूचना के जरिए पदोन्नत किए गए लोगों को रिट याचिका में चुनौती नहीं दी गई और न ही उन्हें रिट याचिका का नोटिस दिया गया, हालांकि, उन्हें कार्यवाही में पक्षकार बनाया गया था। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, राज्य सरकार ने एसीएस वर्ग-I अधिकारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की, जिसमें सभी 129 पदोन्नत लोगों को 45 सीधी भर्ती वाले अधिकारियों से वरिष्ठ दिखाया गया। याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि उक्त वरिष्ठता सूची को कभी चुनौती नहीं दी गई और उसे प्राप्त कर लिया गया।

9. 26 जून, 2003 को, उच्च न्यायालय की विद्वान एकल पीठ ने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यद्यपि चयन की डी प्रक्रिया 1986 के संशोधन से बहुत पहले शुरू की गई थी, लेकिन सरकार ने नियमों तक कोई नियुक्ति नहीं करने का फैसला किया था। संशोधन किया गया. इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष एक रिट अपील दायर की, जिसे 26 अगस्त, ई 2006 को इस निष्कर्ष पर अनुमति दी गई कि सीधी भर्ती की वरिष्ठता

और पदोन्नतियों को असंशोधित नियमों द्वारा शासित किया जाएगा चयन प्रक्रिया 1986 के संशोधन से पहले शुरू की गई थी। तदनुसार, राज्य सरकार को एफ कोटा नियम लागू करके पदोन्नत लोगों और सीधी भर्ती वाले लोगों की वरिष्ठता तय करने और 1986 के सभी 45 सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता 45 पदोन्नत लोगों के ठीक नीचे तय करने का निर्देश दिया गया था, जिन्हें एसीएस वर्ग में पदोन्नत किया गया था। मैं सेवा करता हूँ. याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि उन्हें रिट अपील के बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि उन्हें इसकी सूचना नहीं दी गई थी। 2006 की समीक्षा याचिका संख्या 92 और 93 जी 9 नवंबर, 2006 को 12 प्रमोटियों द्वारा दायर की गई थीं

याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर कहा कि उन्हें रिट अपील का नोटिस नहीं दिया गया था। इसके बाद, 13 सितंबर, 2006 को डिवीजन बेंच ने समीक्षा याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और 26 अगस्त, 2006 को पारित फैसले और आदेश एच के संचालन पर रोक लगा दी। इसके बाद, 25 सितंबर, 2006, डिवीजन बेंच ने 13 सितंबर, 2006 के अपने पहले के आदेश को संशोधित किया और निर्देश दिया कि अंतरिम आदेश के अनुसार अधिकारियों की पोस्टिंग, यदि कोई हो, केवल न्यायालय की अनुमति से होगी।

10. 13 नवंबर, 2006 को, राज्य सरकार ने इस मामले में अपना जवाबी हलफनामा दायर किया और इस बात से संतुष्ट होने पर कि समीक्षा याचिकाकर्ताओं को रिट अपील का नोटिस नहीं दिया गया था, डिवीजन बेंच ने उन्हें रिट अपील में अपना हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी। और उस पर गुण-दोष के आधार पर समीक्षा याचिकाओं के साथ दोबारा सुनवाई की गई। यह रिट अपील और समीक्षा याचिकाओं की दोबारा सुनवाई पर है कि 2007 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 19188 में लगाया गया आदेश 23 मई, 2007 को पारित किया गया।

11. रिट अपील में दायर अपने जवाबी हलफनामे में, राज्य सरकार ने रिट अपील का विरोध करते हुए कहा कि एसीएस क्लास- I और एसीएस क्लास- II अधिकारियों के विलय पर वरिष्ठता, राज्य द्वारा सही ढंग से तय की गई थी। पक्षों की ओर से की गई दलीलों पर विचार करने के बाद, डिवीजन बेंच ने रिट अपील की अनुमति देते हुए, अधिकारियों को 1960 के नियम 4 द्वारा निर्धारित कोटा के संदर्भ में प्रत्येक स्रोत से भर्ती के लिए वर्ष 1986 में उपलब्ध रिक्तियों का पता लगाने का निर्देश दिया। नियम और कोटा और रोटा नियमों का पालन करते हुए रिक्तियों को चक्रित करके उनकी वरिष्ठता को पुनर्गठित करना। डिवीजन बेंच के उक्त आदेश को इस याचिका में चुनौती देते हुए, इस न्यायालय ने 12 नवंबर, 2007 को पार्टियों को नोटिस जारी किया और यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

12. विशेष अनुमति याचिका के समर्थन में उपस्थित होते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विजय हंसारिया ने सबसे पहले वरिष्ठता से संबंधित 1960 के नियमों के नियम 19 का उल्लेख किया, जो इस प्रकार है: वरिष्ठता: (1) सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता नियम 5 के उप-नियम (5) के तहत तैयार या अनुमोदित सूचियों में योग्यता के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

नियम 8. यदि सदस्य नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर अपनी नियुक्ति ग्रहण करते हैं। बशर्ते कि यदि किसी सदस्य को सार्वजनिक प्रकृति की परिस्थितियों या उसके नियंत्रण से परे कारणों से 15 दिनों की उक्त अवधि के भीतर शामिल होने से रोका जाता है, तो राज्यपाल इसे 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं। यदि अवधि इतनी नहीं बढ़ाई गई है और सेवा का सदस्य नियम 15 के उप-नियम (2) के तहत बढ़ाई गई अवधि के भीतर शामिल होता है, तो उसकी वरिष्ठता शामिल होने की तारीख के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

बशर्ते कि नियम 4 के खंड (बी) और (सी) के तहत एक वर्ष में भर्ती किए गए सेवा के सदस्य नियम 4.1 के खंड (ए) के तहत उसी वर्ष और उसी बैच में भर्ती किए गए सदस्यों से वरिष्ठ होंगे।

13. हमारे उद्देश्य के लिए जो महत्वपूर्ण है वह दूसरा है परंतुक जो इंगित करता है कि एक वर्ष में पदोन्नत लोगों की संख्या नियम 4 के खंड

(बी) और (सी) के तहत सदस्यों से वरिष्ठ होंगे जिनकी एक ही वर्ष और एक ही समय में नियम 4 के खंड (ए) के तहत बैच सीधी भर्ती द्वारा भर्ती की जाती है= दूसरे परन्तुक की भाषा नियम 19 स्पष्ट एवं असंदिग्ध है कि एक वर्ष में नियम 4 के तहत उम्मीदवारों को उच्च पद पर पदोन्नत किया जाएगा जिनकी एक ही वर्ष और उसी में उम्मीदवारों से वरिष्ठ 1960 के नियम 4 के खंड (ए) के तहत बैच भर्ती किए गए।

14. इसके बाद श्री हंसारिया ने हमारा ध्यान नियम 26 की ओर आकर्षित किया, जो यह प्रावधान है कि "वरिष्ठ ग्रेड टाइम स्केल में पदोन्नत सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता उस क्रम में होगी जिसमें उनके नाम उस ग्रेड में पदोन्नति के उद्देश्य से नियम 25 के उप नियम (2) के तहत चयन बोर्ड द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं।" विद्वान वकील ने नियम 27 का भी हवाला दिया, जिसमें राज्य के राज्यपाल को इस बात से संतुष्ट होने पर कि किसी भी नियम के संचालन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हुई है, किसी भी नियम से छूट देने या ढील देने का अधिकार दिया गया था। श्री हंसारिया ने प्रस्तुत किया कि इसके बाद संशोधन अधिनियम 21 जुलाई, 1986 को अधिनियमित किया गया, जिसके तहत नियम 4 में भी संशोधन किया गया, राज्यपाल को पदोन्नत किए जाने वाले एसीएस क्लास- II अधिकारियों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप, एसीएस क्लास- I अधिकारियों की भर्ती के

संबंध में कोटा प्रणाली बंद कर दी गई थी। श्री हंसारिया के अनुसार, कोटा प्रणाली टूट गई थी, जिससे संशोधन की आवश्यकता थी।

15. श्री हंसारिया ने तर्क दिया कि नियमों के तहत याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति द्वारा सीधी भर्ती के लंबे समय बाद नियुक्ति की गई थी और इसलिए, पदोन्नत लोगों पर वरिष्ठता नहीं दी जा सकती थी। श्री हंसारिया ने कहा कि इस याचिका में जो सबसे महत्वपूर्ण था वह भर्ती का सवाल नहीं था, बल्कि उन लोगों के साथ वरिष्ठता कैसे निर्धारित की जानी थी जिन्हें पहले पदोन्नत किया गया था। प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या भर्ती के समय लागू होने वाले वरिष्ठता संबंधी नियम भी वरिष्ठता का निर्धारण करेंगे, भले ही बाद में नियमों में बदलाव किया गया?

16. श्री हंसारिया ने प्रस्तुत किया कि चूंकि कोटा और रोटा नियम का वर्षों से पालन नहीं किया गया था, इसलिए इसे 1960 के नियमों में संशोधन के आधार पर बंद कर दिया गया था जो 21 जुलाई, 1986 से प्रभावी हो गए थे। हालांकि, उक्त संशोधनों को चुनौती दी गई थी उत्तरदाताओं द्वारा, बाद में ऐसी चुनौती छोड़ दी गई। उपरोक्त के बावजूद, उच्च न्यायालय ने अपील में अंतिम निर्णय पर पहुंचने में गलती से असंशोधित नियमों पर भरोसा किया। श्री हंसारिया ने आग्रह किया कि जब 1986 के संशोधन द्वारा कोटा से संबंधित नियमों को बंद कर दिया गया था, तो उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ दोनों की

भर्ती के बाद 21 जुलाई, 1986 को लागू हुए संशोधित नियमों का पालन न करके गलती की। यहाँ उत्तरदाताओं. श्री हंसारिया ने तर्क दिया कि भले ही कोटा नियम लागू माना जाता है, लेकिन लंबे समय तक पालन नहीं किए जाने के कारण यह टूट गया था, संशोधित नियमों को लागू करके वरिष्ठता तय की जानी थी।

17. श्री हंसारिया ने तब आग्रह किया कि यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि सीधी भर्ती वाले उस तारीख से नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते जिस दिन उनके चयन से पहले सीधी भर्ती के लिए कोटा में रिक्ति हुई थी, जो सिद्धांत था 1960 के नियमों के नियम 4(बी) के परंतुक में, यथासंशोधित, शामिल किया गया।

18. इस संबंध में, श्री हंसारिया ने सूरज प्रकाश गुप्ता और अन्य मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया। बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य और अन्य। [(2000) 7 एससीसी 561], जिसमें वही प्रश्न विचार के लिए आया और इस न्यायालय ने पाया कि सेवा न्यायशास्त्र में, एक सीधी भर्ती केवल अपनी नियमित नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता का दावा कर सकती है, न कि उस तारीख से जब वह भी नहीं थी। सेवा में पैदा हुआ. उत्तरांचल राज्य एवं अन्य में इस न्यायालय के निर्णय का भी संदर्भ दिया गया था। बनाम दिनेश कुमार शर्मा [(2007) 1 एससीसी 683], जहां सूरज प्रकाश गुप्ता के मामले (सुप्रा) में पहले के फैसले को

दोहराया गया था और इस बात पर फिर से जोर दिया गया था कि पदोन्नति पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी पिछले वर्ष की वरिष्ठता नहीं मिल सकती है, लेकिन मिलेगी वरिष्ठता उस वर्ष की जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है। इसी तर्ज पर श्री हंसारिया द्वारा कई डी निर्णयों का भी हवाला दिया गया, जिनका संदर्भ आवश्यकता पड़ने पर दिया जाएगा

19. श्री हंसारिया ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने संशोधित नियमों पर भरोसा करने के बजाय 1960 के नियमों के नियम 4 के असंशोधित प्रावधानों एफ पर भरोसा करने में त्रुटि की थी, जो कि कोटा नियमों के बाद से उत्तरदाताओं के मामले के लिए प्रासंगिक थे। वरिष्ठता दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होने पर यह टूट गया।

20. प्रतिवादी क्रमांक 1 से 8 तक एफ का प्रतिनिधित्व करते हुए विद्वान अधिवक्ता श्री पार्थिव गोस्वामी ने बताया कि नियम 4(1) सेवा में भर्ती की विधि प्रदान करता है और उक्त नियम के प्रावधान में कुल रिक्तियों का 50% प्रदान किया गया है। किसी दिए गए वर्ष में असम सिविल सेवा (वर्ग- II) के पुष्टि किए गए सदस्यों की पदोन्नति द्वारा भरा जाना था। इसके अलावा, नियम 19(1) जी में प्रावधान है कि पदोन्नत व्यक्ति एक ही वर्ष और एक ही बैच में नियुक्ति के मामले में सीधी भर्ती से वरिष्ठ होंगे। श्री गोस्वामी ने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने 21 जुलाई, 1986 को नियम 4 में संशोधन किया और राज्यपाल को एच समायोजित किए जाने

वाले पदोन्नतियों की संख्या निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया, लेकिन जैसा कि प्रभाग द्वारा सही बताया गया है खंडपीठ ने कहा कि संशोधित नियम सीधी भर्ती वाले ए पर लागू नहीं होंगे जिनकी चयन प्रक्रिया असंशोधित नियमों के तहत शुरू हो गई है।

21. श्री गोस्वामी ने प्रस्तुत किया कि उनके लिए आरक्षित कोटा से अधिक नियुक्त पदोन्नतियों को केवल तदर्थ के रूप में वर्णित किया जा सकता है और ऐसे तदर्थ पदोन्नति के आधार पर ऐसे पदोन्नतियों को वरिष्ठता नहीं दी जा सकती है। अपनी दलीलों के समर्थन में श्री गोस्वामी ने उत्तरांचल फॉरेस्ट रेंजर्स एसोसिएशन में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया। (सीधी भर्ती) बनाम यूपी राज्य [(2006) 10 एससीसी 346], जिसमें उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी और यह आगे माना गया था कि 1991 में नियुक्त किए गए पदोन्नत लोग सीधे भर्ती किए गए लोगों पर वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते थे, जिन्हें 1990 में पूर्व समय पर नियुक्त किया गया था।

22. इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ एन.टी. में भी दिया गया था। डेविन कट्टी बनाम कामताका लोक सेवा आयोग [(1990) 3 एससीसी 157], जिसमें यह माना गया था कि नियम या आदेश में संशोधन से पहले प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में की गई नियुक्ति आम तौर पर संशोधन से प्रभावित नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, जहां चयन प्रक्रिया

एक विज्ञापन जारी करके आवेदन आमंत्रित करके शुरू की जाती है, वहां चयन को आम तौर पर उस समय प्रचलित नियम या आदेश द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। कई अन्य निर्णयों का भी हवाला दिया गया जहां समान सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। श्री गोस्वामी ने प्रस्तुत किया कि तत्काल मामले में चयन की प्रक्रिया संशोधन लागू होने से पहले शुरू हो गई थी और चूंकि यह माना गया था कि संशोधित नियमों को केवल संभावित संचालन दिया जा सकता है, इसलिए चयन की प्रक्रिया असंशोधित नियमों के तहत शुरू होगी। उसके तहत जारी रखा जाएगा और पूरा किया जाएगा। श्री गोस्वामी ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से दी गई दलीलें कि चयन संशोधित नियमों के अनुसार होगा, स्थापित कानून के विपरीत है और इसलिए, खारिज किए जाने योग्य है।

23. हमने प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है संबंधित पक्षों की ओर से ए और द्वारा उद्धृत निर्णय उन्हें। इस एसएलपी में मुद्दा इस सवाल तक ही सीमित है कि क्या संशोधित 1960 के नियम संशोधन से पहले शुरू की गई चयन प्रक्रिया में भर्ती किए गए व्यक्तियों की वरिष्ठता को नियंत्रित करेंगे। यह विवादित नहीं है कि 1960 के नियमों के असंशोधित नियम 4 के संदर्भ में एसीएस क्लास- I और एसीएस क्लास II अधिकारियों की प्रत्येक श्रेणी में 30 पदों को भरने के लिए 22 मई, 1984 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था और एक

लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। 5 जून, 1984 और 1 अगस्त, 1985 के बीच उक्त नियमों के तहत एपीएससी द्वारा आयोजित

उक्त लिखित परीक्षा का परिणाम 22 सी फरवरी, 1986 को घोषित किया गया था। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के संबंध में एपीएससी द्वारा 25 अप्रैल, 1986 से 30 मई, 1986 तक मौखिक परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बाद अनुशंसित उम्मीदवारों की एक सूची प्रस्तुत की गई एपीएससी ने 22 जून, 1986 को सरकार को सूचित किया। यह भी विवादित नहीं है कि इसके तुरंत बाद 21 जुलाई, 1986 को, 1960 के नियमों के नियम 4(1) और नियम 4(1)(बी) के प्रावधानों में संशोधन किया गया, जिसके तहत कोटा प्रणाली को खत्म करने की मांग की गई और राज्यपाल को किसी दिए गए क्षेत्र में पदोन्नति के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों की संख्या निर्धारित करने का विवेक दिया गया।

24. घटनाओं की कालानुक्रमिक सूची से यह स्पष्ट है कि एसीएस क्लास-I और एसीएस क्लास-II अधिकारियों की प्रत्येक श्रेणी में 30 पदों को भरने के लिए चयन की प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन के प्रकाशन के साथ शुरू हुई जो कि प्रकाशित हुई थी। 22 मई, 1984. इसके अनुसरण में, लिखित परीक्षाएँ भी आयोजित की गईं और लिखित परीक्षाओं का परिणाम 22 फरवरी, 1986 को घोषित किया गया और मौखिक परीक्षा के पूरा होने के बाद, एपीएससी द्वारा अनुशंसित जी

उम्मीदवारों की एक सूची प्रस्तुत की गई। सरकार ने 22 जून, 1986 को। नियम 4 में संशोधन बाद में 21 जुलाई, 1986 को किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की ओर से प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण यह है कि एक बार प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी।

कैलेंडर वर्ष में उपलब्ध रिक्तियों पर कोटा लागू कर छ.ग इस बीच नियमों में संशोधन किया गया। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रिट अपील और समीक्षा याचिकाओं पर दोबारा सुनवाई करते हुए 26 अगस्त, 2006 को पहले व्यक्त किए गए विचारों को दोहराया, जिसमें कहा गया कि सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों की वरिष्ठता चयन के रूप में असंशोधित नियमों द्वारा शासित होगी। प्रक्रिया 1986 के संशोधनों से पहले शुरू की गई थी। नतीजतन, डिवीजन बेंच ने यह भी माना कि पदोन्नत लोगों और सीधी भर्ती के बीच वरिष्ठता 1960 के नियमों के नियम 4 के तहत प्रत्येक स्रोत से भर्ती के लिए निर्धारित कोटा के आधार पर और रोटा चयनकर्ताओं की सीमा तक निर्धारित की जानी थी। उनके कोटे में रिक्तियां, जैसा कि नियमों के नियम 4(1) के प्रावधान में परिकल्पित है, जैसा कि वे 1986 के संशोधनों से पहले थीं। डिवीजन बेंच. तदनुसार, 24 अगस्त, 2006 को अपने पहले के फैसले में संशोधन किया और उपरोक्त संशोधन के साथ एसीएस क्लास I अधिकारियों की अनंतिम वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया और अधिकारियों को उक्त निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता को फिर से निर्धारित करने का निर्देश दिया। उपरोक्त निर्णय पर पहुंचते समय, डिवीजन बेंच को

डॉ. के. रामुलु और अन्य मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करने का अवसर मिला। बनाम डॉ. एस. सूर्यप्रकाश राव एवं अन्य। [(1997) 3 एससीसी 59], जिसमें जो प्रश्न विचाराधीन था वह यह था कि क्या सरकार प्रासंगिक तिथि पर मौजूदा रिक्तियों को नहीं भरने का निर्णय लेने की हकदार थी जब तक कि संशोधन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। इस न्यायालय ने एपी अधीनस्थ सेवा नियमों के नियम 4 पर विचार करने के बाद माना कि उक्त नियम का उद्देश्य यह था कि सभी पात्र उम्मीदवारों पर नियमों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने माना कि सरकार नियमों में प्रस्तावित संशोधन लागू होने से पहले किसी भी रिक्तियों को न भरने का सचेत निर्णय लेने की हकदार थी।

25. जबकि पहली नज़र में के. रामुलु के मामले (सुप्रा) में निर्णय तत्काल मामले के तथ्यों के बराबर प्रतीत हो सकता है, फिर भी एक अंतर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जबकि वर्तमान मामले में मौजूदा नियमों और चयनितों की एक सूची के तहत चयन की प्रक्रिया शुरू की गई थी एपीएससी द्वारा भी उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी, के. रामुलु के मामले में (सुप्रा) सरकार ने केवल संशोधित नियम लागू होने तक रिक्तियों को नहीं भरने का निर्णय लिया था। के. रामुलु के मामले में (सुप्रा) किसी रिक्ति को भरने के उद्देश्य से आरओ प्रक्रिया शुरू की गई थी। बी ऐसी परिस्थितियों में, जहां किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए आमंत्रित या साक्षात्कार या चयनित नहीं किया गया था, जैसा कि किया

गया है वर्तमान मामले में किया गया, इस न्यायालय ने सही ही माना कि सरकार इन्हें न भरने का निर्णय लेने में सक्षम थी रिक्त पद। सी 26. इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है कि नीतिगत मामले के रूप में सरकार उचित कारणों से रिक्तियों को न भरने का सचेत निर्णय ले सकती है, लेकिन साथ ही, असंशोधित नियमों के तहत चयन की प्रक्रिया शुरू करने के बाद, वह ऐसा नहीं कर सकती है। उसका मानना है कि वह अभी भी पुराने नियमों के तहत शुरू की गई प्रक्रिया के अनुसार चयनित उम्मीदवारों में से व्यक्तियों की डी नियुक्तियां नहीं करने का हकदार है। दरअसल, मौजूदा मामले में, एपीएससी द्वारा की गई सिफारिश 22 जून, 1986 को सरकार को सौंपी गई थी। संशोधित नियम 21 जुलाई, 1986 को लागू हुए जिससे कोटा प्रणाली को खारिज कर दिया गया। ऐसी स्थिति में, हमारे विचार में, के. रामुलु के मामले (सुप्रा) में निर्णय नहीं हो सकता इस मामले के तथ्यों पर लागू किया जाए।

27. हम श्री हंसारिया से सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि उच्च न्यायालय ने असंशोधित पर भरोसा करके गलती की है चूंकि कानून में यह भली-भांति तय किया गया है कि चयन की जो प्रक्रिया तत्कालीन नियमों के आधार पर शुरू हुई थी, वह उक्त नियमों के तहत जारी रहेगी, भले ही इस बीच नियमों में संशोधन किया गया हो। तदनुसार, सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता, इसमें कोई संदेह नहीं है, नियम 19 के तहत शासित होगी, लेकिन नियम 19 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए चयन प्रक्रिया

को नियम 4 के तहत पूरा किया जाना है। जिन रिक्तियों के लिए विज्ञापन दिया गया था

1984 में प्रकाशित असंशोधित नियम 4 के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा भरने का निर्देश दिया गया था जिसमें प्रावधान किया गया था पदोन्नत और सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के बीच कोटा के लिए। तदनुसार, वर्ष 1986 के लिए उक्त कोटा प्रणाली को ध्यान में रखते हुए 129 पदोन्नतियों की सूची में से 45 सीधी भर्ती वालों को पहले 45 पदोन्नतियों के ठीक नीचे रखा गया।

28. हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं श्री गोस्वामी द्वारा वेल को ध्यान में रखते हुए दोहराया गया है स्थापित सिद्धांत है कि एक बार चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है भर्ती के मौजूदा नियमों के आधार पर, उक्त नियम इसके बावजूद, चयन प्रक्रिया को नियंत्रित करना जारी रहेगा कोई भी संशोधन जो उक्त नियमों में इस बीच में प्रभावी हो सकता है ।

29. इसलिए, उच्च न्यायालय के निर्णय में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार, विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी जाती है, लेकिन कोस्ट के संबंध में किसी भी आदेश के बिना।

विशेष अनुमति याचिका खारिज.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ज्योति के सोनी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।